मिथीलेश कुमार सिंह

बनाम

राजस्थान राज्य

(रिट याचिका (सीआरएल) सं. 240/2011)

11 दिसंबर, 2014

[टी. एस. ठाकुर, आदर्श कुमार गोल और आर. भानुमती, जे. जे.]

जाँच-स्थानांतरण-स्थानीय पुलिस से केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सी. बी. आई.)-एक कॉलेज की लड़की की रहस्यमय मौत के मामले में-लड़की के पिता (याचिकाकर्ता) द्वारा माँगा गया-यह कहते हुए कि मौत वरिष्ठ छात्रों द्वारा रैगिंग का परिणाम थी और जाँच एजेंसी के निष्कर्षों में कमियाँ और विरोधाभास थे-आयोजित किया गयाःप्रति बहुमतःमामले की संवेदनशीलता और याचिकाकर्ता द्वारा बताई गई परिस्थितियों को देखते हुए, जांच को स्थानीय पुलिस से सी. बी. आई.-प्रति अल्पसंख्यक को स्थानांतरित करने की आवश्यकता हैःवर्तमान मामले में, सामग्री से पता चलता है कि स्थानीय पुलिस द्वारा उचित जांच की गई थी-सी. बी. आई. को उकसाना केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है-वर्तमान मामले में सी. बी. आई. द्वारा जांच की कोई विशेष स्थिति नहीं है।

जाँच-निष्पक्षता और औचित्य-के लिए आवश्यकता-आयोजितःप्रति ठाकुर, जे.:न्यायाधीश के प्रशासन की एक प्रतिकूल प्रणाली में, मुकदमे की निष्पक्षता के लिए जांच की निष्पक्षता सबसे पहली आवश्यकता है।

जाँच-एक अभिकरण से दूसरी अभिकरण में स्थानांतरण-न्यायालय द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंड-आयोजित किए गएःप्रति ठाकुर, जे.:अदालत को अपनी असाधारण

शक्ति का प्रयोग करते हुए जांच को केवल तभी स्थानांतरित करना चाहिए जब घटिया या पक्षपातपूर्ण जांच के कारण न्यायाधीश के पीड़ित होने की उचित आशंका हो-पीड़ितों या उनके अगले रिश्तेदारों की संवेदनशीलता पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं है-हस्तांतरण की पहचान किसी भी अन्य विचार से अधिक स्थानांतरित व्यक्ति की कथित स्वतंत्रता है।

रिट याचिका को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

प्रमुख राय टी. एस. ठाकुर, जे. द्वारा दी गई

1. निष्पक्ष और उचित जाँच के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। न्यायाधीश के प्रशासन की एक प्रतिकूल प्रणाली में, मुकदमे की निष्पक्षता के लिए जांच की निष्पक्षता सबसे पहली आवश्यकता है।पक्षपातपूर्ण, एकतरफा या पक्षपातपूर्ण जांच पर आधारित मुकदमा शायद ही निष्पक्ष हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वाइल परीक्षण स्वयं प्रक्रियात्मक रूप से सही हो सकता है, इसका सार और उद्देश्य एक अनुचित या अप्रभावी जांच द्वारा दूषित किया जा सकता है। [पैरा 3] [1369-डी-एफ]

2. यह केवल तभी होता है जब घटिया या पक्षपातपूर्ण जांच के कारण न्यायाधीश के पीड़ित होने की उचित आशंका होती है कि न्यायाधीशालय हस्तक्षेप कर सकता है और अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अपराध के पीड़ितों या उनके निकटतम परिजन संवेदनशीलता ऐसी स्थितियों में पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं है। जब तक न्यायालय स्थानांतरण के लिए प्रार्थना के पीछे कोई साजिश नहीं देखता है, तब तक इसे केवल यह सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए कि सच्चाई का पता चला है। स्थानांतरिती की पहचान किसी भी अन्य विचार की तुलना में स्थानांतरितीकर्ता की कथित स्वतंत्रता है। सत्य की खोज किसी भी जांच

का अंतिम उद्देश्य है और इसे स्वतंत्र एजेंसी से बेहतर कौन कर सकता है।[पैरा 9] [1373-ई-एच; 1374-ए-बी]

3. एक बार जब न्यायाधीशालय उपलब्ध सामग्री पर संतुष्ट हो जाता है कि इस तरह का पाठ्यक्रम किसी मामले में न्यायाधीश के उद्देश्य को बढ़ावा देगा, तो स्थानांतरण का आदेश दिया जा सकता है। वर्तमान मामले में कॉलेज की युवा छात्रा की मौत की परिस्थितियां जांच का विषय बन गई हैं। यह मुद्दा न केवल एक अमूल्य मानव जीवन के नुकसान के कारण संवेदनशील है, बल्कि उन कारणों के कारण भी संवेदनशील है जिन्हें इस घृणित संबंध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका और लिखित प्रस्तुतियों में जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया है, साथ ही सुनवाई के दौरान इस अदालत के समक्ष जिन दलीलों का आग्रह किया गया था, वे निर्णायक हो भी सकते हैं या नहीं भी, लेकिन उन परिस्थितियों पर सी. बी. आई. जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा उपयुक्त रूप से गौर करने की आवश्यकता है ताकि एक अधूरी, उदासीन या अप्रभावी जांच न्यायाधीश की विफलता की ओर ले जाए। इसलिए, जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाता है। इसलिए, जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया जाता है।[पारस 12,13 और 14] [1375-सी-एच]

मनु शर्मा बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2010) 6 एस. सी. सी. 1:2010 (4) एस. सी. आर. 103; निर्मल सिंह काहलों बनाम पंजाब राज्य (2009) 1 एस. सी. सी. 441:2008 (14) एससीआर 1049; सासी थॉमस अन्य राज्य और अन्य (2006) 12 एससीसी 421:2006 (9) पूरक एससीआर 450; ज़हिरा हबीबुल्ला एच. शेख और अन्र बनामगुजरात राज्य और अन्य (2004) 4 सेक 158:2004 (3) एस. सी. आर. 1050; बाबूभाई अन्य गुजरात राज्य

और अन्य। (2010) 12 एससीसी 254:2010 (10) एससीआर 651; पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य अन्यलोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समिति, पश्चिम बंगाल अन्य (2010) 3 एससीसी 571:2010 (2) एस. सी. आर. 979; लैंडर 9. अन्य पंजाब राज्य (1994) 6 एस. सी. सी. 275; आर. एस. सोधी अधिवक्ता अन्य यू. पी. राज्य और अन्य। 1994 (पूरक) (1) एस. सी. सी. 143; पंजाब राज्य अन्य सी. बी. आई. (2011) 9 एस. सी. सी. 182:2011 (11) एस. सी. आर. 281; सुब्रत चट्टोराज बनाम भारत संघ (2014) 8 एस. सी. सी. 768-पर भरोसा किया।

अदर्श कुमार गोएल, जे. द्वारा (सहमत)

4. यह सच है कि राज्य पुलिस से सी. बी. आई. को जांच के हस्तांतरण की प्रार्थना की अनुमति केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में दी जा सकती है जब राज्य पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच किसी भी बाहरी प्रभाव या अन्यथा के कारण विश्वास को प्रेरित नहीं करती है। कोई कच्चा लोहा मापदंड नहीं हो सकता है और क्या कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न हुई है, यह न्यायालय द्वारा किसी विशेष मामले की तथ्य स्थिति का अवलोकन करके निर्धारित किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, कॉलेज के अधिकारियों या स्थानीय पुलिस को दोष देना आवश्यक नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ता की आशंका और जांच के हस्तांतरण के लिए उनकी प्रार्थना को भी खारिज नहीं किया जा सकता है। एक छात्रा की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार, लड़की का बयान दर्ज नहीं किया गया था, भले ही ऐसा किया जा सकता था और इस प्रकार, सच्चाई सामने नहीं आई है। इन परिस्थितियों में, यह उचित होगा कि मामले की जांच सी. बी. आई. द्वारा की जाए। [पैरा 4] [1377-डी-जी]

पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा समिति, पश्चिम बंगाल और अन्य (2010) 3 धारा 571:2010 (2) एस. सी. आर. 979-अनुसरण किया गया।

अल्पमत का विचारः आर. भानुमति, जे. द्वारा

5. याचिकाकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज करने पर, पुलिस ने यू/एस 306 भा.दं.सं. मामला दर्ज किया है। गवाहों के बयान, चिकित्सा रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों के आधार पर, राज्य पुलिस के जांच अधिकारी ने पाया कि यह आत्महत्या का मामला है और अंतिम रिपोर्ट दायर की। मामले की सामग्री से पता चलता है कि उचित जांच की गई है। [पैरा 9] [1381-सी, डी-ई]

6. सी. बी. आई. को जाँच सौंपने का आदेश केवल एक असाधारण स्थिति में दिया जा सकता है और इस तरह के आदेश को केवल इसलिए नियमित रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एक पक्ष ने अस्पष्ट आरोप लगाए हैं। वर्तमान मामला ऐसी असाधारण स्थिति नहीं है जिसकी सी. बी. आई. द्वारा विशेष जाँच की आवश्यकता है। रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। [पैरा 10 और 11] [1381-एफ; 1382-ई-एफ]

पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य अन्य लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा समिति, पश्चिम बंगाल और अन्य। (201 ओ) 3 सेक 571:201 ए (2) एस. सी. आर. 979-अनुसरण किया गया।

मामला कानून संदर्भ

टी. एस. ठाकुर जे. के निर्णय में	भरोसा किया	पैरा 3
2010 (4) एस. सी. आर. 103	भरोसा किया	पैरा 4
2008 (14) एस. सी. आर. 1049	भरोसा किया	पैरा 5

2006 (9) पूरक एस. सी. आर. 450	भरोसा किया	पैरा 6
2004 (3) एस. सी. आर. 1050	भरोसा किया	पैरा 7
2010 (10) एस. सी. आर. 651	भरोसा किया	पैरा 8
2010 (2) एस. सी. आर. 979	संदर्भित	पैरा 9
(1994) 6 एस. सी. सी. 275	भरोसा किया	पैरा 10
1994 पूरक (1) एस. सी. सी 143	भरोसा किया	पैरा 10
2011 (11) एस. सी. आर. 281	भरोसा किया	पैरा 11
(2014) 8 एस. सी. सी. 768	भरोसा किया	पैरा 11

आदर्श कुमार गोयल जे के निर्णय में,

2010 (2) एस. सी. आर. 979	पालन किया	पैरा 4

आर. बानुमति जे. के निर्णय में

2010 (2) एस. सी. आर. 979	पालन किया	पैरा 10

आपराधिक मूल क्षेत्राधिकार रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 240/ 2011

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

के. राधाकृष्णन, सीनियर एड. एम. मीनाक्षी लेखी, मुकेश चौहान, हरीश पांडे, गायक उपाध्याय, जितेंद्र बी त्रिपाठी, रंजन नारायण, मो. खराती, बी. वी. बलराम दास, ई. सी. अग्रवाल, बलदेव अत्रेया, दीपक गुप्ता, अरविंद कुमार शर्मा, अमित शर्मा, संदीप सिंह, दीपक गोयल, वी. एन. रघुपति, अधिवक्ता उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय टी. एस. ठाकुर, जे. द्वारा दिया गया

1. मुझे अपनी कुलीन बहन जे. भानुमति द्वारा प्रस्तावित आदेश को पढ़ने का लाभ मिला है। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि मैं खुद को राजी नहीं समर्थ हूं एल) रिट याचिका को खारिज करने के लिए सहमत हूं जो मेरी राय में न केवल एक युवा कॉलेज छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत द्वारा जुड़े मामले में जांच की निष्पक्षता को छूते हुए संवेदनशील मुद्दे उठते हैं, बल्कि यह भी कि क्या यह घृणित घटना उसके वरिष्ठ सहयोगियों द्वारा मृतक की रैगिंग का परिणाम थी, जिसके बारे में सूचित किए जाने के बावजूद कॉलेज के अधिकारी इद्वारा रोकने में विफल रहे। याचिकाकर्ता द्वारा बताई गई परिस्थितियों को देखते हुए इस अदालत के लिए यह निर्णय लेना जल्दबाजी होगी कि स्थानीय पुलिस द्वारा की गई जांच निष्पक्ष थी या मृतक ने चार मंजिला कॉलेज के छात्रावास से कूदकर आत्महत्या कर ली क्योंकि वह एक अवांछित गर्भधारण कर रही थी।याचिकाकर्ता, जो मृतक के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ने जांच एजेंसी के निष्कर्षों में कुछ कमियों और विरोधाभासों को इंगित करने का प्रयास किया है, जिनकी मेरी राय में सच्चाई का पता लगाने के लिए सीबीआई जैसी बाहरी एजेंसी द्वारा निष्पक्ष प्रयास में जांच की जानी चाहिए।

2. पृष्ठभूमि में तथ्य मेरी विद्वान बहन द्वारा उनके द्वारा प्रस्तावित आदेश में बताए गए हैं। इसलिए, उन्हें फिर से दोहराने का कोई उद्देश्य नहीं होगा।यह विवाद में नहीं है कि मृतक और उसकी बहन को कॉलेज में फ्रेशर्स के रूप में भर्ती कराया गया था। यह भी विवाद में नहीं है कि वह कॉलेज के छात्रावास की चौथी मंजिल से गिरने के कारण घायल हो गई थी, जहां वह अपनी बहन के साथ रह रही थी। यह भी एक विवादास्पद तथ्य है कि उन्हें पहले डुलेट अस्पताल और बाद में सवाई मान सिंह अस्पताल ले जाया गया था।यह भी स्वीकार किया जाता है कि इमारत से गिरने के तीन दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। एक निष्पक्ष और उचित जांच की मांग यह थी कि क्या वह वरिष्ठों द्वारा रैगिंग के कारण गिर गई, जैसा कि याचिकाकर्ता ने आरोप

लगाया था या वह आत्महत्या करने के लिए कूद गई थी। प्रतिवादी का मामला जिसमें राजस्थान राज्य, पुलिस और वह कॉलेज शामिल है जहाँ वह पढ़ रही थी, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने एक अवांछित गर्भावस्था के कारण आत्महत्या की थी जिसे वह वहन कर रही थी।उस संस्करण के समर्थन में अस्पताल के चिकित्सा रिकॉर्ड पर भरोसा किया जाता है, जिससे पता चलता है कि (ए) वह 14 सप्ताह की गर्भवती थी और (बी) उसकी मृत्यु के 24 घंटों के भीतर गर्भावस्था का गर्भपात कर दिया गया था।रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने मृतक के गर्भ से भ्रूण को हटाने के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया था, इसके बावजूद कि उस प्रक्रिया का पालन नहीं होने पर होने वाले परिणामों के बारे में परामर्श दिया गया था।चिकित्सा रिकॉर्ड से यह प्रतीत होता है कि भ्रूण के पिता की सहमति के अभाव में डॉक्टरों द्वारा भ्रूण को नहीं हटाया गया था। मृतक।आरोप यह है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट स्पष्ट रूप से गर्भावस्था या 14 सप्ताह के भ्रूण की उपस्थिति को स्थापित नहीं करती है।याचिकाकर्ता के अनुसार यह इस कहानी को गलत साबित करता है कि मृतक गर्भवती थी जिससे उसे आत्महत्या करने का संभावित कारण मिल सकता है। याचिकाकर्ता का मामला यह भी है कि रैगिंग द्वारा उत्पीड़न की शिकायत कॉलेज के अधिकारियों से की गई थी जिन्होंने मामले में कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता का आरोप है कि कॉलेज अधिकारियों की लापरवाही के कारण मृतक लगभग आधे घंटे तक जमीन पर पड़ा रहा।यह भी आरोप है कि हालांकि मृतक को गंभीर चोटें आई थीं, जो अंततः घातक साबित हुई, लेकिन कॉलेज के अधिकारियों द्वारा पुलिस में कोई शिकायत या रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। अस्पताल में रहने के दौरान मृतक का कोई बयान या मृत्यु की घोषणा दर्ज नहीं की गई थी, भले ही वह होश में और उन्मुख थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, मेडिकल रिकॉर्ड गढ़ा गया है क्योंकि कॉलेज का स्वामित्व और संचालन राजस्थान राज्य में प्रभावशाली लोगों द्वारा किया जाता है, इस तथ्य के अलावा कि अस्पताल में एक वरिष्ठ डॉक्टर प्रतिवादी में से एक

से संबंधित है।कॉलेज के अधिकारियों पर मृतक की छोटी बहन पर किसी को भी सही तथ्यों का खुलासा नहीं करने के लिए दबाव डालने का भी आरोप है अन्यथा उसे परिणाम भुगतने होंगे। सभी ने याचिकाकर्ता को बताया कि वह राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच से पूरी तरह से असंतुष्ट और निराश है।यही कारण है कि वह सच्चाई को सामने लाने के लिए प्रकरण की निष्पक्ष और उचित जांच के लिए प्रार्थना करता है ताकि न्यायाधीश न केवल जांच के स्तर पर बल्कि मुकदमे में भी किया जा सके जो जांच की निष्पक्षता पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

3. निष्पक्ष और उचित जाँच के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। न्यायाधीश के प्रशासन की एक प्रतिकूल प्रणाली में, मुकदमे की निष्पक्षता के लिए जांच की निष्पक्षता सबसे पहली आवश्यकता है।पक्षपातपूर्ण, एकतरफा या पक्षपातपूर्ण जांच पर आधारित मुकदमा शायद ही निष्पक्ष हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि परीक्षण स्वयं प्रक्रियात्मक रूप से सही हो सकता है, लेकिन इसका सार और उद्देश्य एक अनुचित या अप्रभावी जांच द्वारा दूषित किया जा सकता है।इस न्यायालय ने कई फैसलों में जांच की निष्पक्षता के महत्व पर जोर दिया है।इस संबंध में, मनु शर्मा बनाम दिल्ली राज्य (2010) 6 एस. सी. सी. 1 में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें इस न्यायालय ने जांच की निष्पक्षता पर विचार करते हुए कहा था।

> "भारत में आपराधिक न्यायाधीश प्रशासन प्रणाली मानवाधिकारों और मानव जीवन की गरिमा को बहुत उच्च स्तर पर रखती है।हमारे न्यायशास्त्र में एक अभियुक्त को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है, कथित अभियुक्त निष्पक्षता और सच्ची जांच और निष्पक्ष सुनवाई का हकदार है और अभियोजन पक्ष से अपराध के मुकदमे में संतुलित भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है।कानून के मूल नियम

का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच विवेकपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित होनी चाहिए।ये हमारे आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत हैं और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 में निहित संवैधानिक जनादेश के अनुरूप हैं।"

4. निर्मल सिंह काहलों बनाम पंजाब राज्य (2009) 1 एस. सी. सी. 441 में, इस न्यायालय ने कहा कि जांच की निष्पक्षता न केवल अभियुक्त के लिए बल्कि पीड़ित के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस अदालत ने कहाः

"अभियुक्त को निष्पक्ष जाँच का अधिकार है। निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक आरोपी के मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए संगत हैं। लेकिन कानून और आदेश, सार्वजनिक आदेश और समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए राज्य का एक बड़ा दायित्व है। इस प्रकार अपराध का शिकार व्यक्ति निष्पक्ष जाँच का समान रूप से हकदार है।"

5. इसी प्रभाव के लिए सासी थॉमस अन्य राज्य और अन्य मामलों में इस न्यायालय का निर्णय है। (2006) 12 एस. सी. सी. 421, जिसमें जांच की निष्पक्षता को कानून के शासन के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में मान्यता दी गई थी। अदालत ने कहाः

"जाँच अधिकारी की ओर से उचित और निष्पक्ष जाँच कानून के शासन की रीढ़ है। एक गंभीर अपराध की उचित और प्रभावी जांच और विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, बहुत महत्व रखता है क्योंकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य को साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री का संग्रह आवश्यक हो जाता है। दुर्भाग्य से,

अपीलकर्ता के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया है। जब मृत्यु किसी संदिग्ध परिस्थिति में हुई हो और विशेष रूप से जब उसे दफनाने का प्रयास किया गया हो।यदि मृत शरीर स्पष्ट रूप से एक गलत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर जल्दबाजी में सहायता करता है, तो यह उम्मीद की जाती थी कि शव को निकालने पर, राज्य के जांच अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्यों का निष्पक्ष रूप से पालन करेंगे।"

6. ज़हिरा हबीबुल्ला एच. शेख और एक अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2004) 4 एस. सी. सी. 158 का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें न्यायाधीशालय ने कहा कि यदि जांच निष्पक्ष नहीं है तो न्यायाधीश बी पीड़ित बन सकता है। न्यायालय ने टिप्पणी कीः

"जब जाँच एजेंसी अभियुक्त की मदद करती है, तो गवाहों को झूठी गवाही देने की धमकी दी जाती है और अभियोजक इस तरह से कार्य करता है जैसे कि वह अभियुक्त का बचाव कर रहा हो, और अदालत केवल एक दर्शक के रूप में कार्य कर रही थी और जब कोई निष्पक्ष सुनवाई नहीं होती है, तो न्यायाधीश पीड़ित बन जाता है।"

7. मैं अंत में बाबूभाई अन्य गुजरात राज्य और अन्य मामलों में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकता हूं। (2010) 12 एस. सी. सी., 254, डी. जहाँ न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में कानूनी स्थिति को दोहरायाः

"आपराधिक अपराध की जाँच आपत्तिजनक विशेषताओं या दुर्बलताओं से मुक्त होनी चाहिए जो वैध रूप से अभियुक्त की ओर से शिकायत का कारण बन सकती है कि जाँच अनुचित थी और एक गुप्त उद्देश्य के

साथ की गई थी। जाँच अधिकारी का यह भी कर्तव्य है कि वह किसी भी आरोपी को किसी भी तरह की शरारत और उत्पीड़न से बचने के लिए जाँच करे। जाँच अधिकारी को निष्पक्ष और सचेत होना चाहिए ताकि साक्ष्य के मनगढ़ंत होने की किसी भी संभावना को खारिज किया जा सके और उसके निष्पक्ष आचरण से उसकी वास्तविकता के बारे में किसी भी संदेह को दूर किया जा सके। जाँच अधिकारी "अभियोजन पक्ष के मामले को ऐसे साक्ष्य के साथ मजबूत करने के लिए नहीं है जो अदालत को दोषसिद्धि दर्ज करने में सक्षम बना सके, बल्कि वास्तविक अप्रमाणित सत्य को सामने लाने के लिए है।"(आर. पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 866; जमुना चौधरी और अन्य बनाम बिहार राज्य ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1822 और महमूद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 69)

40. इसलिए, यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जांच किसी पक्ष की मदद करने के उद्देश्य से की गई है, तो न्यायालय आगे की जांच के लिए निर्देश दे सकता है और आम तौर पर फिर से जांच के लिए नहीं।

41. अभिव्यक्ति का अर्थ आम तौर पर सामान्य होता है और इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कोई अपवाद हो सकता है।इसका मतलब है कि अधिकांश मामलों में लेकिन हमेशा नहीं।"आम तौर पर "असाधारण" या "विशेष परिस्थितियों" को शामिल नहीं किया जाता है।(वीडियोःकैलाश चंद्र अन्य भारत संघ ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1346; आयशर ट्रैक्टर्स लिमिटेड, हरियाणा अन्य सीमा शुल्क आयुक्त,

बॉम्बे ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 196; और ए. पी. राज्य अन्य सरमा राव और अन्य। ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 137)

42. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि असाधारण परिस्थितियों में, न्यायाधीशालय आपराधिक न्यायाधीश के गर्भपात को रोकने के लिए, यदि आवश्यक समझता है, तो वह नए सिरे से जांच के लिए निर्देश दे सकता है जिसमें मामला असाधारण परिस्थितियों को प्रस्तुत आदेशता है।

45. न केवल निष्पक्ष सुनवाई बल्कि निष्पक्ष जांच भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत गारंटीकृत संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा है। इसलिए, जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और विवेकपूर्ण होनी चाहिए क्योंकि यह कानून के शासन की न्यूनतम आवश्यकता है। जाँच एजेंसी को दागी और पक्षपातपूर्ण तरीके से जाँच करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जहाँ न्यायाधीशालय के गैर-हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप अंततः न्यायाधीश की विफलता होगी, वहाँ न्यायाधीशालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसी स्थिति में, यह न्यायाधीश के हित में हो सकता है कि उच्च न्यायाधीशालय द्वारा चुनी गई स्वतंत्र एजेंसी एक नई जांच करे।"

8. निष्पक्ष अन्य उचित जांच का इतना महत्व होने के कारण, इस न्यायालय ने कई अलग-अलग तथ्य स्थितियों से उत्पन्न होने वाले कई मामलों में दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत राज्य/अधिकार क्षेत्र पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो को जांच स्थानांतरित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। इस तरह के स्थानांतरण का निर्देश देने की इस न्यायालय की शक्ति को दयापूर्वक कोई चुनौती नहीं दी गई थी अन्य

मेरी राय में यह सही है कि क्या इस न्यायालय के पास स्थानांतरण का निर्देश देने का अधिकार क्षेत्र है, इस प्रश्न का पश्चिम बंगाल राज्य में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा आधिकारिक रूप से निपटारा किया गया है। लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समिति, पश्चिम बंगाल अन्य अन्य (2010) 3 एससीसी 571।

9. फिर भी शक्ति की उपलब्धता और उसका प्रयोग दो अलग-अलग मामले हैं। यह न्यायालय केवल पूछने के लिए जांच के हस्तांतरण का निर्देश नहीं देता है और न ही स्थानांतरण का निर्देश केवल अहंकार को संतुष्ट करने या ऐसी जांच में रुचि रखने वाले पक्ष की प्रतिष्ठा को सही साबित करने के लिए दिया जाता है।स्थानांतरण का आदेश दिया जाना चाहिए या नहीं, यह निर्णय न्यायालय की संतुष्टि पर निर्भर करता है कि क्या किसी मामले के तथ्य और परिस्थितियां ऐसे आदेश की मांग करती हैं।सभी मामलों में सार्वभौमिक अनुप्रयोग के लिए कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया गया है या संभवतः निर्धारित किया जा सकता है।प्रत्येक मामला स्पष्ट रूप से अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर करेगा।महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय इस सिद्धांत के प्रति संवेदनशील रहता है कि स्थानांतरण का आदेश केवल इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि कोई पक्ष अन्वेषक को किसी दिए गए निष्कर्ष पर ले जाना चाहता है।यह केवल तभी होता है जब घटिया या पक्षपातपूर्ण जांच के कारण न्यायाधीश के पीड़ित होने की उचित आशंका होती है कि न्यायाधीशालय हस्तक्षेप कर सकता है और अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।अपराध के पीड़ितों या उनके निकटतम परिजन संवेदनशीलता ऐसी स्थितियों में पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं है। आखिरकार, किसी बाहरी एजेंसी को जांच के स्थानांतरिती का मतलब यह नहीं है कि स्थानांतरितीकर्ता एजेंसी अनिवार्य रूप से अपराध करने में किसी को भी कम गलत तरीके से फंसाएगी।यह विशेष रूप से तब होता है जब किसी बाहरी एजेंसी को

हस्तांतरण का आदेश दिया जाता है जिसे प्रभाव, दबाव और खिंचाव से स्वतंत्र माना जाता है जो आम बात है जब राज्य पुलिस कुछ महत्वपूर्ण मामलों की जांच करती है। ऐसे मामलों में बाहरी एजेंसी में स्थानांतरण की मांग करने वाले पक्ष का विश्वास स्वयं उस एजेंसी की इस तरह के या इसी तरह के अन्य विचारों से स्वतंत्रता पर निर्भर करता है।यह इस प्रकार है कि जब तक न्यायालय स्थानांतरण के लिए प्रार्थना के पीछे कोई साजिश नहीं देखता है, तब तक इसे केवल यह सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए कि सच्चाई का पता चला है।स्थानांतरिती की पहचान किसी भी अन्य विचार की तुलना में स्थानांतरितीकर्ता की कथित स्वतंत्रता है।सत्य की खोज किसी भी जांच का अंतिम उद्देश्य है और इसे स्वतंत्र एजेंसी से बेहतर कौन कर सकता है।

10. यह कहने के बाद कि हमें खुद को याद दिलाने की आवश्यकता है कि इस न्यायालय ने कई विविध स्थितियों में स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग किया है।लैंडर 9. बनाम पंजाब राज्य (1994) 6 एस. सी. सी. 275 में इस न्यायालय ने तब भी जाँच सी. बी. आई. को हस्तांतरित कर दी जब जाँच की निगरानी राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही थी। आर. एस. सोधी अधिवक्ता बनाम यू. पी. राज्य और अन्य में भी ऐसा ही है। 1994 (पूरक) (1) एस. सी. सी. 143 जांच तब भी स्थानांतरित की गई थी जब राज्य पुलिस एक पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी की देखरेख में आवश्यक काम कर रही थी और राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त किया था। इस अदालत ने कहा कि पुलिस भले ही ईमानदारी से जांच करे, लेकिन उसमें विश्वसनीयता की कमी होगी क्योंकि मुठभेड़ में शामिल पुलिस बल के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर थे, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की मौत हो गई थी।

इस अदालत ने कहा कि सी. बी. आई. को स्थानांतरण, "मृतक के रिश्तेदारों सहित सभी संबंधित लोगों को आश्वासन देगा कि एक स्वतंत्र एजेंसी मामले को देख रही है।"

11. पंजाब राज्य बनाम सी. बी. आई. (2011) 9 एस. सी. सी. 182 में इस न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें इस न्यायालय ने सेक्स स्कैंडल के संबंध में राज्य पुलिस से सी. बी. आई. को जांच स्थानांतरित करने के आदेश को बरकरार रखा, जबकि उच्च न्यायालय ने डी. आई. जी. और उनके अधिकारियों की टीम द्वारा की गई जांच की सराहना की थी।सुब्रत चट्टोराज बनाम भारत संघ (2014) 8 एस. सी. सी. 768 में, इस न्यायालय ने सत्ता और प्रभाव या राजनीतिक प्रभाव के उच्च पदों पर बैठे कई प्रभावशाली व्यक्तियों की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में चिट फंड घोटाले को राज्य पुलिस से सी. बी. आई. को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

12. यह कहने के लिए पर्याप्त है कि स्थानान्तरण का आदेश विभिन्न स्थितियों में दिया गया है, लेकिन ऐसा करते समय न्यायालय द्वारा लागू परीक्षण हमेशा यह रहा है कि क्या स्थानांतरण के लिए निर्देश, आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सत्य की खोज की प्रक्रिया को विश्वसनीय बनाने की दृष्टि से आवश्यक था। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अदालत ने शायद ही कभी जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने के अनुरोध को संदेह के साथ देखा है। अदालत की ओर से उन मामलों में पीड़ितों या उनके परिवारों को राहत देने में कोई अनिच्छा नहीं है, जहां हस्तक्षेप की मांग की जाती है, और न ही स्थानांतरण का आदेश देने से पहले राज्य पुलिस की ओर से दुरुपयोग या उपेक्षा का एक कच्चा लोहा मामला बनाने के लिए स्थानांतरण की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के लिए यह आवश्यक है।एक बार जब न्यायाधीशालय उपलब्ध सामग्री पर संतुष्ट हो जाता है कि इस तरह का पाठ्यक्रम किसी मामले में न्यायाधीश के उद्देश्य को बढ़ावा देगा, तो स्थानांतरण का आदेश दिया जा सकता है।

13. इस मामले में कॉलेज की युवा छात्रा की मौत की परिस्थितियां जांच का विषय बन गई हैं। यह मुद्दा न केवल एक अमूल्य मानव जीवन के नुकसान के कारण संवेदनशील है, बल्कि उन कारणों के कारण भी संवेदनशील है जिन्हें इस घृणित संबंध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।याचिकाकर्ता ने रिट याचिका और लिखित प्रस्तुतियों में जिन परिस्थितियों का उल्लेख किया है और सुनवाई के दौरान हमारे सामने जिन दलीलों का आग्रह किया गया था, वे उनके महत्व में निर्णायक हो भी सकते हैं या नहीं भी, लेकिन उन परिस्थितियों पर सी. बी. आई. जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा उपयुक्त रूप से गौर करने की आवश्यकता है ताकि एक अधूरी, उदासीन या अप्रभावी जांच न्यायाधीश की विफलता की ओर ले जाए।

14. परिणामस्वरूप, मैं इस याचिका और जयपुर के बागरू पुलिस स्टेशन में दर्ज एफ. आई. आर. सं.463/ 2011 में जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सीधे स्थानांतरित प्राथमिकी ने की अनुमति देता हूं।सी. बी. आई. का निदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि जांच को संभालने के लिए सक्षम अधिकारियों को सौंपा गया है और कानून के अनुसार ऐसी अनुवर्ती कार्रवाई की जाए जिसकी अनुमति हो। मैं यह स्पष्ट करता हूं कि मैंने मामले के गुण-दोष या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घटना से जुड़े किसी व्यक्ति की संलिप्तता के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं की है। इस आदेश में किए गए अवलोकनों को केवल यह तय करने के उद्देश्य से किया गया माना जाएगा कि हस्तांतरण का आदेश उचित है या नहीं। कोई लागत नहीं।

आदर्श कुमार गोएल, जे।

1. मैंने अपने सम्मानित भाई माननीय टी. एस. ठाकुर, जे. और मेरी सम्मानित बहन माननीय आर. भानुमति, जे. द्वारा प्रस्तावित आदेशों पर विचार किया है, जिसमें

एफ. एल. की जांच के हस्तांतरण के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना के औचित्य के मामले में अलग-अलग विचार रखे गए हैं। एफ. आई आर. सं.463/ 2011 राजस्थान पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) को पुलिस स्टेशन बागरू, जयपुर, राजस्थान में पंजीकृत।

2. यह मामला 81 सितंबर, 2011 को एक युवा छात्रा की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से संबंधित है। जयपुर में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में भर्ती मृतक को संस्थान के वरिष्ठ छात्रों द्वारा परेशान किए जाने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की खंड 306 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसे चौथे विमान में ले जाया गया और उसे नीचे की ओर देखा गया, भले ही वह डर गई थी और उसे चक्कर आ रहे थे। वह जमीन पर गिर गई और घायल हो गई।उसकी उचित देखभाल नहीं की गई और चोटों और लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हो गई। सच्चाई को छिपाने और कॉलेज की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, यह दिखाने के लिए गलत मेडिकल रिकॉर्ड तैयार किया गया था कि वह चौदह सप्ताह की गर्भवती थी, जिसके कारण उसने चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। याचिकाकर्ता के अनुसार, स्थानीय पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की और मामले को आत्महत्या का बताते हुए गलत तरीके से अंतिम रिपोर्ट दायर की।तदनुसार, याचिकाकर्ता ने जांच को सी. बी. आई. में स्थानांतरित करने के निर्देश के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके और न्यायाधीश किया जा सके।दूसरी ओर, कॉलेज के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस का मामला यह है कि उसने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी और कॉलेज के अधिकारियों ने उसके इलाज के लिए हर संभव कदम उठाए।रिलायंस को इस प्रभाव के लिए मेडिकल रिपोर्ट पर भी रखा गया है कि वह चौदह सप्ताह की गर्भवती थी और इस वजह से वह अपना जीवन समाप्त करना चाहती थी।उसके गिरने के परिणामस्वरूप, गर्भावस्था का

गर्भपात कर दिया गया था, लेकिन वह भ्रूण को हटाने के लिए सहमत नहीं थी, जिसके कारण सेप्टिसीमिया हो गया और उसकी मृत्यु हो गई।

3. हमने इस मुद्दे पर चिंता से विचार किया है। इस स्तर पर, एकमात्र सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ता की इस आशंका का कोई आधार है कि स्थानीय पुलिस द्वारा जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती है और क्या सी. बी. आई. में स्थानांतरण के लिए उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया जाना चाहिए।

4. यह सच है कि राज्य पुलिस से सी. बी. आई. को जांच के हस्तांतरण की प्रार्थना की अनुमति केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में दी जा सकती है जब राज्य पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच किसी भी बाहरी प्रभाव के कारण या अन्यथा विश्वास को प्रेरित नहीं करती है जैसा कि पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम सी. बी. आई. में किया गया है। लोकतांत्रिक अधिकार संरक्षण समिति, पश्चिम बंगाल और अन्य।कोई कच्चा लोहा मापदंड नहीं हो सकता है और क्या कोई असाधारण स्थिति उत्पन्न हुई है, यह न्यायालय द्वारा किसी विशेष मामले की तथ्य स्थिति का अवलोकन करके निर्धारित किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, हम कॉलेज के अधिकारियों या स्थानीय पुलिस को दोष देना आवश्यक नहीं समझते हैं, लेकिन हम याचिकाकर्ता की आशंका और जांच के हस्तांतरण के लिए उनकी प्रार्थना को भी अस्वीकार करने में असमर्थ हैं।एक छात्रा की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है।याचिकाकर्ता के अनुसार, लड़की का बयान दर्ज नहीं किया गया था, भले ही ऐसा किया जा सकता था और इस प्रकार, सच्चाई सामने नहीं आई है।इन परिस्थितियों में, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह उचित होगा कि मामले की जांच सी. बी. आई. द्वारा की जाए।

5. तदनुसार, इस याचिका की अनुमति दी जाती है और एफ. आई आर. 463/2011 पुलिस स्टेशन बागरू, जयपुर में पंजीकृत को सी. बी. आई. को स्थानांतरित कर दिया गया है।

6. याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

आर. भानुमति, जे.

1. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमन, जयपुर की बी. टेक प्रथम वर्ष की छात्रा एस. एस. की मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) द्वारा एक स्वतंत्र बी जांच शुरू करने के लिए परमादेश रिट की मांग की गई है, जिसने अपने छात्रावास के कमरे की पांचवीं मंजिल की रेलिंग से गिरने से हुई चोटों के कारण दम तोड़ दिया।

2. याचिकाकर्ता का संक्षिप्त मामला इस प्रकार हैः- याचिकाकर्ता बिहार का निवासी है और विशाखापत्तनम में काम कर रहा है।याचिकाकर्ता की दो बेटियों, एस. एस. और टी. एस. ने राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमन, जयपुर में 25.8.2011 पर B.Tech में प्रवेश लिया और उन्हें कॉलेज के छात्रावास में भर्ती कराया गया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि 2.9.2011 पर उसकी दो बेटियों को दूसरे वर्ष की दो वरिष्ठ लड़कियों द्वारा खरोंच कर दिया गया था और उसी की सूचना उसकी बेटी एस. एस. ने उसे फोन पर दी थी।एस. एस. के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसने अपनी मौसी को घटना के बारे में सूचित करने के लिए फोन किया था।आगे की पूछताछ के लिए, उनकी चाची (राज कुमारी देवी) छात्रावास गईं और मुख्य वार्डन शालिनी से मिलीं, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि इस मामले को देखा जाएगा और कदम उठाए जाएंगे। कहा जाता है कि 6.9.2011 पर, एस. एस. ने अपनी छोटी बहन टी. एस. को सूचित किया कि वह ठीक नहीं है और इसलिए वह कक्षाओं में नहीं

जाएगी और टी. एस. कॉलेज चली गई। उसी दिन लगभग 1 बजे, यह आरोप लगाया जाता है कि दो वरिष्ठ लड़कियों ने फिर से एस. एस. को चौथी मंजिल की रेलिंग पर चढ़ाकर उसे जमीन की ओर देखने के लिए मजबूर करके रैगिंग के लिए पकड़ा और ऐसा करते हुए, एस. एस. नीचे गिर गई और उसे चोटें आईं, और वह लगभग आधे घंटे तक जमीन पर बनी रही।जब किसी ने उसे देखा, तो उसे "डुलेट अस्पताल" ले जाया गया, जहाँ उसका प्राथमिक उपचार किया गया और उसे सवाई मान सिंह (एस. एम. एस.) अस्पताल, जयपुर भेज दिया गया।याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसकी छोटी बेटी टी. एस. को कॉलेज के अधिकारियों द्वारा धमकी दी गई थी और चेतावनी दी गई थी कि वह रैगिंग के तथ्य का खुलासा न करे अन्यथा उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 161 के तहत दर्ज उनकी छोटी बेटी टी. एस. का बयान जबरदस्ती और उसके और उसकी बहन के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की धमकी के तहत प्राप्त किया गया था।

3. एस. एस. के पैरों और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में भर्ती होने के तीन घंटे बाद होश में आने के बाद, उसने टी. एस. को घटना के बारे में बताया। याचिकाकर्ता 7.9.2011 की शाम को अस्पताल पहुंचा जब मृतक ने उसे घटना के बारे में बताया। 8.9.2011 को शाम 7:30 बजे एस. एस. ने दम तोड़ दिया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस तथ्य के बावजूद कि एस. एस. तीन दिनों तक जीवित रही और पूरी तरह से होश में थी, कॉलेज अधिकारियों के प्रभाव में पुलिस ने एस. एस. याचिकाकर्ता का बयान दर्ज नहीं किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट कॉलेज अधिकारियों के निर्देश और मिलीभगत पर तैयार की गई थी जो गलत आरोप लगा रहे थे और मृतक के चरित्र को दंडित कर रहे थे। याचिकाकर्ता ने न्यायाधीश पाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के

अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष से संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 को लागू करते हुए, याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि उनकी बेटी के साथ गंभीर अन्याय किया गया है जो मूल अधिकार का उल्लंघन है।याचिकाकर्ता का तर्क है कि कॉलेज के अधिकारियों ने पुलिस और अस्पताल के साथ मिलीभगत की है ताकि कॉलेज को रैगिंग के आरोपों से बचाया जा सके।याचिकाकर्ता का तर्क है कि राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच पक्षपातपूर्ण है और इसलिए वह जांच को सी. बी. आई. को सौंपने का निर्देश चाहता है।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4, अर्थात् पुलिस अधिकारियों और राजस्थान राज्य ने अपने जवाबी हलफनामे दायर किए हैं जिसमें कहा गया है कि मृतक की बहन, अन्य दोस्तों, कॉलेज के प्राचार्य, मुख्य वार्डन, वार्डन और अन्य कर्मचारियों और सदस्यों के बयानों में से किसी ने भी रैगिंग की किसी भी घटना का खुलासा नहीं किया है।प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का तर्क है कि मृतक के परिवार के दर्द और पीड़ा को देखते हुए, उन्होंने उचित तरीके से एक निष्पक्ष जांच की ताकि न्यायाधीश के सर्वोत्तम हित को कम किया जा सके। यह माना जाता है कि मामले की जांच वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की गई थी और जांच के दौरान रैगिंग का कोई सबूत नहीं मिला था और यह आत्महत्या का मामला पाया गया था और इस आशय की अंतिम रिपोर्ट मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर की अदालत में दायर की गई थी।

6. प्रत्यर्थी संख्या 5 से 7, अर्थात् कॉलेज के अधिकारियों ने याचिका में प्रत्येक कथन को नकारते हुए जवाबी शपथ पत्र दायर किया।कॉलेज के अधिकारियों के अनुसार, घटना के तुरंत बाद एस. एस. को "डुलेट अस्पताल" ले जाया गया जो परिसर से

मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर है।प्राथमिक उपचार के बाद, एस. एस. को सवाई मान सिंह (एस. एम. एस.) अस्पताल, जयपुर भेजा गया, जहाँ उन्हें आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों ने उनका तत्काल इलाज किया।प्रतिवादी संख्या 5 से 7 ने आगे कहा कि डॉक्टरों द्वारा याचिकाकर्ता को सेप्टीसीमिया और संक्रमण और अन्य जटिलताओं के बारे में सभी जोखिम कारकों के बारे में समझाया गया था यदि एस. एस. के गर्भाशय से अवांछित पदार्थों को नहीं हटाया जाता है।प्रतिवादी का यह भी तर्क है कि कॉलेज के अधिकारियों ने रैगिंग के संबंध में मामले की जांच के लिए 6.9.2011 पर एक समिति का गठन किया और समिति ने पाया कि मृतक को मतली, उल्टी और सिरदर्द जैसी चिकित्सा समस्याएं थीं और रैगिंग की कोई घटना नहीं थी, जैसा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था।यह माना जाता है कि याचिका में लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार और निराधार हैं। प्रतिवादी संख्या 5 से 7 'के अनुसार, पुलिस द्वारा शिकायत की पूरी तरह से जांच की गई और यह पता चलने पर कि रैगिंग का कोई सबूत नहीं था, पुलिस ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जयपुर की अदालत में अंतिम रिपोर्ट दायर की।

7. प्रत्यर्थी संख्या 8, अर्थात् केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ने प्रार्थना की कि तत्काल मामले की जांच राज्य पुलिस पर इस निर्देश के साथ छोड़ी जानी चाहिए कि कुछ तार्किक अंत तक पहुंचने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया जाए क्योंकि तत्काल मामला दुर्लभ मामलों की श्रेणी में नहीं आता है।

8. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनी हैं जिन्होंने रिट याचिका और जवाबी हलफनामों में किए गए संबंधित कथनों को दोहराया है।हमने एस. एस. की मेडिकल रिपोर्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट, राज्य पुलिस द्वारा दायर अंतिम रिपोर्ट और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्रियों का भी अध्ययन किया है।

9. सामग्री के अवलोकन से, यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा 9.9.2011 पर शिकायत दर्ज करने पर, पुलिस ने एफ. एल. में मामला दर्ज किया है। आर. नं. 463/2011 जयपुर के बागरू पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की खंड 306 के तहत। राज्य पुलिस ने मृतक की बहन, अन्य सहपाठियों, कॉलेज के प्राचार्य, मुख्य वार्डन, वार्डन और अन्य कर्मचारियों, डॉक्टरों और सभी संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए।गवाहों के बयान, चिकित्सा रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों के आधार पर, जांच अधिकारी ने पाया कि यह आत्महत्या का मामला है और अंतिम रिपोर्ट दायर की।मैं इसके विवरण में प्रवेश करने से बच रहा हूं, ऐसा न हो कि यह किसी भी पक्ष को प्रभावित कर सकता है।सामग्री पर विचार करने पर, मेरे विचार में, उचित जांच की गई है।

10. यह देखते हुए कि सी. बी. आई. को जांच सौंपने का आदेश केवल एक असाधारण स्थिति में दिया जा सकता है बनाम इस तरह के आदेश को केवल इसलिए नियमित रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि एक पक्ष ने अस्पष्ट आरोप लगाए हैं, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अन्य में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा। लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समिति, पश्चिम बंगाल और अन्य, (2010) 3 धारा 571, पैराग्राफ (70) में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः

> "70. मामला छोड़ने से पहले, हम इस बात पर जोर देना आवश्यक समझते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्तियों के बावजूद, कोई भी आदेश पारित करते समय, न्यायालयों को इन संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग पर कुछ स्वयं की सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। उक्त अनुच्छेदों के तहत शक्ति की प्रचुरता के लिए इसके प्रयोग में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जहां तक किसी मामले में जांच करने के लिए सी. बी. आई. को निर्देश

जारी करने का सवाल है, हालांकि यह तय करने के लिए कोई कठोर दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन बार-बार यह दोहराया गया है कि इस तरह का आदेश नियमित रूप से या केवल इसलिए पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि किसी पक्ष ने स्थानीय पुलिस के खिलाफ कुछ आरोप लगाए हैं।इस असाधारण शक्ति का प्रयोग संयम, सावधानी और असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जहां विश्वसनीयता प्रदान करना और जांच में विश्वास पैदा करना आवश्यक हो जाता है या जहां घटना के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकते हैं या जहां पूर्ण न्यायाधीश करने और मूल अधिकार को लागू करने के लिए ऐसा आदेश आवश्यक हो सकता है।अन्यथा सी. बी. आई. बड़ी संख्या में मामलों से भर जाएगी और सीमित संसाधनों के साथ, गंभीर मामलों की ठीक से जांच करना भी मुश्किल हो सकता है और इस प्रक्रिया में असंतोषजनक जांच के साथ अपनी विश्वसनीयता और उद्देश्य खो सकता है।"

11. अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में, यह मामला ऐसी असाधारण स्थिति नहीं है जिसकी सीबीआई द्वारा विशेष जांच की आवश्यकता है। रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।हालाँकि, याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार उपाय करने की स्वतंत्रता है।

कल्पना के. त्रिपाठी

रिट याचिका को मंजूरी दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।